

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

20
04
26

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता श्री पूर्णेश बोहरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(क)(घ) सपठित धारा 151 सीपीसी पर वकील वादी श्री हनुमान सिंह चौहान व प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादीगण ने उक्त वाद वादग्रस्त भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) के खसरा न. 421 रकबा 0.34 हैक्टर पर पिछले 70-80 वर्षों से काबिज होने से घोषणा खातेदारी का पेश किया है। तथा साथ ही वाद में वर्णित किया है कि नामान्तरकरण सं. 609 दिनांक 19.5.2022 वादीगण के हितो के विरुद्ध स्वीकृत होने से वाद पेश किया है। अपने वाद पत्र में यह भी वर्णित किया की वादीगण के पिताजी और ताउ का नाम श्री जब्बर सिंह जी पुत्र भैरो सिंह था तथा प्रतिवादी सं. 2 से 9 के पिता का नाम जब्बर सिंह पुत्र जयसिंह जी था। प्रतिवादीगण व वादीगण की भूमि पास-पास होने से उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से खीमसिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर जब्बर सिंह पुत्र जयसिंह के वारिसान के नाम दर्ज करने से वादीगण उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध उक्त वाद प्रस्तुति के अधिकारी होने से वाद पेश किया है। इसके विपरित अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 से 3 की दलील है कि वादी स्वयं के कथनो से उक्त वाद में वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने से वादी का वाद विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है इस संबंध में प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानुनी दृष्टांत आरआरडी 2019 पेज 133 में प्रतिपादित सिद्धान्त भी सटिक है क्योंकि वादग्रस्त भूमि के न तो कभी वादी के पिता खातेदार रहे है, एवं न ही वादीगण स्वयं इस भूमि के कभी खातेदार रहे है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रश्न है, इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिससे प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियो में बल होने से वादीगण के उक्त वाद में प्रथम दृष्ट्या वादहेतुक उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वादीगण स्वयं अपने वादपत्र में स्वीकार करते हैं कि वादीगण के ताउ व प्रतिवादीगण के पिता का एक ही नाम था तथा नामान्तरकरण संख्या 609 गलत तौर पर दाखिल व स्वीकृत हुआ। कहीं पर यह वर्णित नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता अथवा दादा के खातेदारी की रही हो। धारा 151 सी.पी.सी. में विधि के प्रावधानो अनुसार न्यायालय इतना लाचार व बेबस नहीं है, कि अकारण ही बिना वाद हेतुक के प्रकरणों में आगे की कार्यवाही करें। जिससे प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रतिवादी अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादीगण द्वारा ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) स्थित भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 0.34 हैक्टर की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. भबूतसिंह पुत्र खीमसिंह
2. केसरसिंह पुत्र खीमसिंह
3. रामसिंह पुत्र खीमसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण जीवदा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी एवं प्रतिनिधि श्री तहसीलदार तहसील कार्यालय बाली जिला पाली (राज)
2. नरपतसिंह पुत्र जबरसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र जबरसिंह
4. उबरा कंवर पुत्री जबरसिंह
5. पंकु कंवर पत्नी स्व जब्बरसिंह
6. मंजु कंवर पुत्री जबरसिंह
7. लील कंवर पुत्री जबरसिंह
8. शोभा कंवर पुत्री जबरसिंह
9. सागर कंवर पुत्री जबरसिंह जाति से राजपूत निवासीगण जीवदा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gems No. 2023/179

वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-04-26 को जारी किया गया।



(दिनेश विश्णोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली